भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1833
जिसका उत्तर मंगलवार 06 मार्च, 2018 को दिया जाना है

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सुदृढ़ करना

1833. श्री आलोक संजर:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सुदृढ़ करने और पूंजीगत वस्तुओं के आयात को कम करने के लिए कोई योजना तैयार की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों के लिए तकनीकी सहायता और चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान आधुनिक औद्योगिक पार्क प्रदान करने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या इस संबंध में कोई व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सुदृढ़ बनाने हेतु कोई योजना नहीं बनाई है। तथापि, 5 वर्षों की अवधि में ।581.22 करोड़ के वित्तीय आवंटन के साथ वर्ष 2014 में सरकार द्वारा " भारतीय केपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने" के लिए एक योजना आरंभ की गई है। इस योजना में केपिटल गुड्स उद्योग को आधारभूत संरचना सहायता और प्रौद्योगिकी संबंधी गहनता को बढ़ाने हेतु अनेक घटक शामिल हैं।

(ग) से (ङ): केपिटल गुड्स सेक्टर में प्रौद्योगिकी उन्नति के लिए सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने कर्नाटक सरकार द्वारा तुमकुर, कर्नाटक में इंटीग्रेटिड मशीन टूल्स पार्क की स्थापना करने के लिए ।125 करोड़ की वित्तीय सहायता अनुमोदित की है। विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) और नियमित रूप से निगरानी सहित प्रस्तावों की जांच करने के बाद स्कीम के अंतर्गत परियोजनाएं मंजूर की जाती हैं।

******